की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपकरण सप्लाई किया है। अतः उत्पादन विशिष्ट क्रयादेशों के लिए हुआ है। भारी इंजीनियरी निगम द्वारा उत्पादित उपकरणों की मांग आवश्यक रूप से इस्पात मिलों के लगाने के कार्यक्रम पर निर्भर है। इस समय भारी इंजीनियरी निगम के भारी मशीनें बनाने के कार्यक्रम की क्षमता 1971-72 के वर्षारम्भ तक बुक की जा चुकी है।

(ङ) और (च). इस्पात कारखने लगाने के कार्यक्रम का निर्धारण करते समय सरकार भारी इंजीनियरी निगम की क्षमता के उपयोग की आवश्यकता का ध्यान रखती है।

12.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Strike by workers of Telco and other engineering concerns.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : (BASTI) : I call the Attention of the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

> The serious situation arising out of strike by 40,000 workers of TELCO and other engineering concerns in Jamshedpur for implementation of Central Board Wage-rates.

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE AND LABOUR EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI JAGJIWAN RAM) : About thirty to thirty five thousand workers of seven major engineering establishments in Jamshedpur have been on strike from the 18th of November, 1969 to press their demand for higher wages. The strike followed a series of as yet inconclusive meeting of the State level tripartite committee set up to go into the matter. This Committee was constituted in pursuance of the unanimous agreement reached at an earlier tripartite meeting held at Patna on the 13th of September, 1969 for the purpose of working out an agreed wage structure for workers in the Engineering Industry in the State of Bihar, in the context of the Report of the Central Wage Board for Engineering Industries. The Wage Board's recommendations not having been unanimous, the approach to implementation has been in terms of State region-wise settlements. The State level Tripartite Committee last met on November 15, 16 and 17, 1969. During the course of these discussions, the Committee was given to understand that the strike at Jamshedpur would take place from the 18th of November 1969, unless the committee was able to bring about a wage settlement before then.

The Labour relation machinery of State Government of Bihar is seized of it. The needed law and order arrangements at Jamshedpur have been provided. The State authorities have appealed to the workers to resume work so that the tripartite negotiations can be carried forward in the proper atmosphere.

We are in touch with the State Government and have advised them to try and bring the parties together for further negotiations.

I will take this opportunity to appeal to the workers to withdraw the strike and to the employers to withdraw their withdrawal from the tripartite negotiations.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : The workers have resorted to this strike because they have failed to get their grievances redressed by other means. It has been stated on and off by the Central Government as well as the State Governments that they would use their good offices and their machinery to see that the wage board awards are implemented. Secondly, is it not a fact that at the present moment the Bihar Assembly stands suspended and, therefore, it is the responsibility of the Central Government to take an active interest in the settlement of this issue ? In this context, may I know whether the representatives of the workers and the management have been called here to see that a settlement is arrived at? I know that they are here but I do not know whether it has been at the instance of the Government of India that they are here. Then, may I have an assurance from the hon. Minister that this matter will be settled by direct initiative of the Central Government so that a large number of workers may

again go back to work ? Most of the gheraos are taking place in this country primarily for the reason that in spite of the fact that the wage board awards are mandatory the management refuses to implement them. Is it a fact that the government machinery is so weak that it cannot exercise its influence to see that the workers' rightful claims are accepted ?

SHRI JAGJIWAN RAM : As I have stated earlier, it is a fact that the recommendation of the wage board was not unanimous. Therefore, at a meeting held here some time back it was decided in consultation with the representatives of workers, employers and the State Governments that efforts should be made by the State Government to have a State-wise or region-wise settlement. The State Government wanted some time to negotiate with the parties at the State level.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : There is no elected government in the State.

SHRI JAGJIWAN RAM: In some States settlements have been effected. Here also when the tripartite negotiations were going on at one stage it appeared that the settlement was within reach. Knowing the area of difference between the employers and the employees, I have no doubt that if a further negotiation takes place a final settlement can be effected in the next week or two. The Advisor of the Bihar Government was here and he had discussions with the officials of the Labour Ministry. One or two representatives of employers were also here; may be they are here even today. Following the break down of the negotiation the representatives of employers wrote to the government that they are withdrawing from the tripartite negotiations. That is why I said that let the workers withdraw the strike and the employers withdraw their withdrawal.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begusarai) : What about victimisation ?

SHRI S. M. BANERJEE : They will victimise every workers. Last time Tatas and others did it.

SHRI JAGJIWAN RAM : It has been our approach that in such cases victimisation should be done a way with. I would still appeal to the workers and employers to sit around a table and discuss the problem and I have have no doubt that the area of difference being very narrow the final settlement can be reached within the course of the next few days.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मन्त्री महोदय यहीं पर ट्रिपार्टाइट मीटिंग क्यों नहीं कर लेते ? सभी दल यहां पर मौजूद हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों के नाम हैं पहले वे तो हो जायं ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा हूं कि तीनों दल यहां पर मौजूद हैं, मन्त्री महोदय उनकी मीटिंग क्यों नहीं कर लेते हैं । शायद मन्त्री जी अपने जवाब को स्पष्ट करना चाहते हैं ।

MR. SPEAKER : I am very sorry. A question can be asked only by the hon. Member calling attention of the Minister. He can get up and say that he is not satisfied.

श्री भोगेन्द्र झा : यह प्राइवेट बात नहीं हो रही है, सदन में हो रही है । सवाल यहां पूछा गया है, हम स्थिति को समझना चाहेंगे, मन्त्री जी स्पष्ट करें ।

MR. SPEAKER : I will have to allow everyone if I depart from the practice.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के इस बयान का स्वागत करता हूं कि उनके बारे में यहां कुछ बात चीत की जायगी । पर मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल वेज बोर्ड मुकर्रर किया था, वह वेजबोर्ड कब मुकर्रर हुआ था, कितने साल उसने काम किया और वह इतने सालों में कोई यूनानिमस रिपोर्ट क्यों नहीं दे पाया । और अब आप कहते हैं कि क्यों कि उसका अवार्ड यूनानिमस नहीं है इस

श्री बलराज मधोक

लिए हम रीजनलवाइज या स्टेटवाइज बात करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर एक इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री ही नहीं है, और इंडस्ट्रीज भी है, और मेहंगाई सब जगह बराबर है तो आप सारे देश के लिए वेज बोर्ड मुकर्रर करके इन्जीनियरिंग वर्कर्स को दो महीने के अन्दर अवार्ड देंगे, और वह अवार्ड सब पर लागू हो, इस पर आप विचार करने के लिए तैयार हैं ?

दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सत्य नहीं है कि प्राइवेट सैक्टर के जो कारखाने बिहार में हैं उनमें काम करने वालों की टर्म्स और कन्डीशन्स पब्लिक सैक्टर के कारखानों से अच्छी हैं। इसलिए सरकार पब्लिक सैक्टर के जो वर्कर्स हैं क्या उनको इस प्रकार के माडल टर्म्स देगी ताकि बाकियों के लिए वह मौडल का काम कर सके

तीसरा सवाल यह है कि ... क्योंकि बिहार में स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट जिम्मेदारी है, इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट यहां पर ट्रिपार्टाइट कानफ्रेंस बुलाए जिसमें केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के प्रतिनिधि रहें, दूसरे ऐम्प्लायर के प्रतिनिधि हों और तीसरे वर्कर्स के प्रतिनिधि हों। इसलिए बजाय पटना के दिल्ली के अन्दर क्या केन्द्रीय सरकार मीटिंग बुलायेगी ताकि दो, तीन दिन के अन्दर इसका फैसला हो जाये ?

श्री जगजीवन राम : जितने सवाल पूछे गए हैं वे तो वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन में मौजूद हैं। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि 1964 में बनाया गया था बीच ... इंटरिम रिलीफ दी थी। उसके बाद जनवरी, 1969 में उसकी फाइनल रिपोर्ट आयी थी। यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि वेज बोर्ड ने सारे देश के लिए एक ही वेज रिकमेन्ड की थी। उन्होंने अलग अलग कारखाने की जो क्षमता है उसको दृष्टिकोण में रख कर के देश के अलग अलग हिस्सों में जो मजदूरी का मान है उसको देख कर के अलग अलग सिफारिशें की थी। इसलिए यह कहना कि स्टेटवाइज करेंगे तो गड़बड़ हो जायेगी, ठीक नहीं है। सारे देश के लिए कोई एक वेतन मान करना मुनासिब नहीं है और उसमें वक्त भी बहुत लगेगा। बिहार में सरकार नहीं है तो इसके इतने ही माने हैं कि पालियामेंट में वहां का प्रश्न लाया जा सकता है। लेकिन बिहार में सरकार न होने से यह माने नहीं होते कि केन्द्रीय सरकार के सभी अफसर वहां जाकर काम करने लगें।

श्री योगेन्द्र शर्मा : लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जमसेदपुर और रांची वेज के मामले में कलकत्ता जोन में है।

श्री जगजीवन राम : यह प्रश्न भी उठाया गया कि यदि ऐम्प्लायर और वर्कर्स के प्रतिनिधि यहां पर हों तो बातचीत कर ली जाय। तो मुझे मालूम नहीं है कि वर्कर्स और ऐम्प्लायर के सभी रिप्रजेन्टेटिव यहां हैं। लेकिन मैं पता लगाऊंगा। अगर ऐम्प्लायर और वर्कर्स के प्रतिनिधि यहां हुए तो एक कोशिश की जायगी कि जल्दी से जल्दी आपस में मिल कर के इस मामले का फैसला करें।

श्री बलराज मधोक : मेरा कहना यह था कि आप स्वयं इनिशियेटिव लेंगे ? इस मामले में आप इनिशियेटिव ले कर वर्कर्स के नुमाइन्दे और एम्प्लायर के नुमाइन्दे यहां बुला कर अपने नेतृत्व में फैसला करा दें ताकि मामला लम्बा न चले। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं वही कह रहा था कि पता लगाऊंगा। अगर आवश्यकता होगी मेरे बीच में पड़ने की तो मैं भी पड़ने में हिचकिचाहट नहीं करूंगा।

SHRI K. N. PANDEY (Padrauna) : Sir, I rise on a point of order. The idea of appointing a wage board was evolved during the Third Plan to maintain industrial peace in the country and to have uniformity in wages. Now, the hon. Minister says that

the States have to negotiate on the wage issue which will mean that each State will have a different wage pattern. How is it in consonance with the idea evolved during the Third Plan ?

MR. SPEAKER : This is no point of order. I request you not to get up on any pretext to raise a point of order. There is no point order.

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि वेज बोर्ड में अलग अलग हिस्सों में जो मजदूरी का मान है उसको देख कर अपनी सिफारिशें की थीं। लेकिन यह जो घटना घटी है इसकी पूरी जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है। कैसे ? वेज बोर्ड ने जोनल तरीके से फैसला करने का सिद्धान्त स्वीकार किया और बंगाल में उसी के अनुसार उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन बिहार सरकार ने नहीं किया। वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जाकर मीटिंग बुलायी। जब बंगाल में वह सिद्धान्त स्वीकार हुआ, और जमशेदपुर भी उसी जोन में आता है तो फिर इतनी देर क्यों की गयी। अक्टूबर के महीने में मैं वहां मौजूद था। अक्टूबर में टिन प्लेट की स्ट्राइक हुई, नवम्बर में वहां की सरकार ने यह ऐश्योरेंस दिया कि 17 तारीख को इंटरिम रिलीफ के बारे में हम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग पटना में करेंगे। पहले स्ट्राइक विड्रा हो। मगर कुछ नहीं हुआ। यह स्ट्राइक बिहार सरकार की वजह से है। यह ईस्टर्न जोन का मामला है जहां पर एम्प्लायर की एक आर्गेनाइजेशन कलकत्ता में भी मौजूद है। वहां तो वेज बोर्ड की जोनल बेसिस वाली सिफारिश के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया लेकिन बिहार में सरकार उसको नहीं करा सकी।

अभी बिहार सरकार ने स्ट्राइक को इलीगल घोषित किया है, और एम्प्लायर ने यह नोटिस दिया है कि वर्कर्स जोइन करें, सरकार भी वही चाहती है कि वर्कर्स जोइन करें। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐम्प्लायर यहां मौजूद हैं, एम्प्लाईज भी यहां मौजूद हैं और बिहार के श्री टी. पी. सिंह, जो ऐडवाइजर हैं, वह भी यहां मौजूद हैं, जो वहां निगोशियेट कर रहे थे। और हमारे मन्त्री जी भी यहां मौजूद हैं अतः वह दो, तीन दिन के अन्दर मीटिंग करा कर इसका फैसला करा दें। यह सम्भव है, वह करा सकते हैं। लेकिन अगर यह नहीं हुआ तो जैसी परिस्थितियां मैंने वहां देखी है, वैसी ही हालत एच. ई. सी. में भी होगी वहां, भी स्ट्राइक होगी और एक भयानक परिस्थिति पैदा होगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी इस सरकार पर होगी।

इसलिए मेरा यही कहना है कि जब सब यहीं मौजूद हैं तो मन्त्री जी दो, तीन दिन के अन्दर निगोशियेशन्स करा कर इसका फैसला करा दें सरकार का यह कहना कि स्ट्राइक को विड्रा कर लें मजदूर यह बिलकुल फिजूल बात है, यह नहीं होगा।

श्री जगजीवनराम : मैंने जवाब दे दिया है, फिर दोहराये देता हूं। जैसा मैंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि ऐम्प्लायर के सभी प्रतिनिधि और वर्कर्स के सभी प्रतिनिधि यहां हैं। मैंने यही कहा कि मैं पता लगाऊंगा। अगर यहां हैं तो अधिकारियों से कहूंगा कि यहां उनको बैठावें और अगर आवश्यकता हुई तो उनको बुलाकर के या वहां पर मिलकर के जल्दी से जल्दी यह मसला तय हो उसका प्रयत्न किया जायेगा।

SHRI JYOTIMORY BASU (Diamond Harbour) : And make a Statement on the floor of the House.

श्री मोहम्मद इस्माइल : अपील न करें, फैसले की तरफ पहले जायें।

अध्यक्ष महोदय : जिनके नाम नहीं हैं कालिंग अटेन्शन मोमन में, आप माफ करें उनको वक्त नहीं दे सकता

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda) : The hon. Minister has himself admitted that the tripartite talks have failed and the workers have gone on strike. He has also said that the recommendations of

[Shrimati Sucheta Kripalani]

the Wage Board were not unanimous, that there were four different recommendations which were conflicting and therefore, the work is more difficult and the tripartite conference has to assume more responsibility and to practically discuss it *de novo* and arrive at a workable solution. Now, the State Government having failed, may I suggest that the Central Government should call the tripartite conference here and assume full responsibilty for bringing about a workable solution ?

He has also very kindly said that he is appealing to the workers to withdraw the strike and also appealing to the employers to participate in the tripartite conference which is very good. I was going to ask him to do that. I would now ask the Minister to make a firm announcement that none of the workers will be victimised. On that basis the workers should be asked to resume work. A firm date should be announced for the tripartite conference and the Central Government should assume entire responsibility for bringing about a settlement in the matter.

SHRI JAGJIWAN RAM : At this stage I would reply that the State Government cannot be completely kept out of the picture. It should not be forgotten that it is a matter in the State's sphere. Therefore, the State Government will have to deal with this question. But we will give our good offices as I have already said.

SHRI S. M. BANERJEE : Mr. Bhagat went to Calcutta during the jute mills strike. I would request you to kindly intervene effectively. Otherwise TATAS will never implement. I can assure you.

SHRI JAGJIWAN RAM : As I have said, we will give our good offices to see that the parties are brought to the negotiation, table and negotiations take place and a final settlement is reached within a very short time. (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: Bihar representatives are also here.

SOME HON. MEMBERS : What about victimisation ?

SHRI JAGJIWAN RAM : I have say about that also.

12.22 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

Registration of Electors (Third Amendment) Rules, 1969

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) :

I beg to lay on the Table a copy of the Registration of Electors (Third Amendment) Rules, 1969, published in Notification No. S O. 4540 (English version) and S O. 4541 (Hindi version) in Gazette of India dated the 6th November, 1969 under sub-section (3) of section 28 of the Representation of the People Act, 1950. [*Placed in Library*. See No. L T. 2084/69].

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :--

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Indian Soldiers (Litigation) Amendment Bill, 1969, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th November, 1969."

INDIAN SOLDIERS (LITIGATION). AMENDMENT BILL

As Passed by Rajya Sabha

SECRETARY : Sir, I lay on the Table of the House the Indian Soldiers (Litigation) Amendment Bill, 1969, as passed by Rajya Sabha.

12.23 hrs.

WAKF (AMENDMENT) BILL-*CONTD.*

MR. SPEAKER : Now we will take up the next item-Item No. 5. Further consideration of Wakf (Amendment) Bill. The time